

43

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर
प्रकरण क्रमांक / 18 निगरानी

निगरानी-4633/2018/टीकमगढ/पुनर्विचार

S.K. Khare
(S.K. Khare)

प्रस्तुत! दिनांक 27-7-18

27-7-18

- 1- लखन लाल पुत्र श्री रतन लाल अहिरवार
आयु-57 वर्ष, व्यवसाय-कृषि कार्य
- 2- सियाराम पुत्र श्री गोकल अहिरवार
आयु-65 वर्ष, व्यवसाय-कृषि कार्य
- 3-देवेन्द्र पुत्र श्री ग्यादीन अहिरवार
आयु-30 वर्ष, व्यवसाय-कृषि कार्य
निवासीगण-ग्राम धवा वॅगरा
तहसील-निवाडी, जिला टीकमगढ, म0प्र0
.....आवेदकगण
बनाम
1- मोती लाल कुम्हार पुत्र श्री कन्हैया लाल
आयु-59 वर्ष, निवासी-ग्राम शक्ति भैरो
तहसील-निवाडी, जिला टीकमगढ, म0प्र0
.....अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, विरुद्ध आदेश दिनांक 01/06/18 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचर कलॉ निवाडी, जो प्रकरण क्रमांक 65/अ-12/2017-18 में पारित कर अनावेदक का सीमांकन आवेदन स्वीकार कर सीमांकन, पंचनामा, फील्ड बुक और सूचना-पत्र स्वीकृत किया है। सीमांकन आदेश की प्रमाणित प्रति निगरानी के साथ संलग्न की जाकर अनेक्चर ए/1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त तथ्य

- 1- यह कि, आवेदकगण शासकीय कृषि भूमि खसरा क्रमांक नं.-1185/1 स्थित ग्राम शक्ति भैरो तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ, म0प्र0 पर लगभग 50 वर्षों से वास्तविक रूप से काबिज होकर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। जिस पर आवेदकगण को शासन द्वारा अर्थ दण्ड भी लिया गया है।
- 2- यह कि, अनावेदक द्वारा उक्त शासकीय कृषि भूमि खसरा क्रमांक 1185/1 का राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचर कलॉ निवाडी के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 02/04/2018 को किया जाना कहा जाता है। जिस आधार पर श्रीमान् राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक


43

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4633/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

लखनलाल विरुद्ध मोतीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-10-2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक लखनलाल की ओर से अभिभाषक श्री भूपेन्द्र माहौर उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तरीचर कलाँ के सीमांकन आदेश दिनांक 01-06-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी पर निर्णय लिया जाना है । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 	<p style="text-align: right;">  22.10.18 (आर.के. जैन) सदस्य </p>

2